PURVANCHAL PRAHARI, Guwahati, 25.9.2017
Page No. 8, Size:(12.89)cms X (13.43)cms.

एक खरब डालर के करीब है देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था : प्रसाद

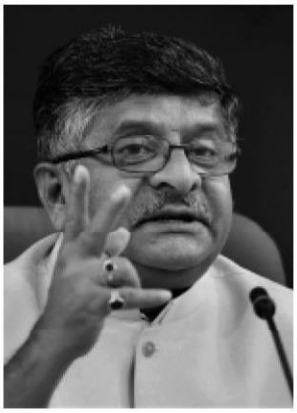

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि भारत औद्योगिक और उद्यमिता क्रांति (इंडस्ट्रियल और इंट्रप्रन्योरशिप रिवाल्यूशन) का लाभ नहीं उठा सका, लेकिन अब हम डिजिटल क्रांति से वंचित नहीं रहना चाहते। प्रसाद ने आज यहां एक समारोह में कहा कि विदेशी नियंत्रण की वजह से जहां हमारा देश औद्योगिक क्रांति के लाभ नहीं उठा सका, वहीं लाइसेंस परमिट कोटा राज की वजह से 60 से 90 के दशक में दुनिया में हुई उद्यमिता क्रांति के फायदों से भी वंचित रह गया, लेकिन हम डिजिटल क्रांति से वंचित नहीं रहना चाहते। उन्होंने भारत में उभरती डिजिटल दुनिया विषय पर कैपिटल फाउंडेशन सोसायटी के वार्षिक व्याख्यान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया अभियान के तहत होने वाली डिजिटल क्रांति विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए है और इसका उद्देश्य इस वर्ग को सशक्त बनाना है। प्रसाद ने कहा कि हम तकनीक को आंदोलन बनाना चाहते हैं जो कि फायती, समावेशी और विकासपरक होनी चाहिए। हम डिजिटल इको स्पेस बनाना चाहते हैं जिससे डिजिटल समावेश हो। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक खरब डालर की होने जा रही है। 80 देशों के 200 शहरों में भारतीय आईटी कंपनियां हैं। इनमें 30 लाख से ज्यादा भारतीय सीधे तौर पर और एक करोड़ 30 लाख परोक्ष रूप से जुड़े हैं जिनमें एक तिहाई महिला उद्यमी हैं। प्रसाद ने डिजिटल गवर्नेंस को अच्छा शासन बताते हुए कहा कि आधार एक डिजिटल पहचान है, भौतिक पहचान नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार पैन और मोबाइल नंबर की तरह ही मोटर ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ने की परियोजना पर काम कर रही है और उसे अंतिम रूप दे रही है। इससे कोई फर्जी तरीके से दूसरा लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा। प्रसाद ने कहा कि देश में 30 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोलकर उन्हें आधार और मोबाइल फोन से जोड़ा गया और राशन, गैस की सब्सिडी तथा मनरेगा की मजदूरी सीधे उनके खाते में दी जाने लगी। ऐसा करने से दो साल में कमीशनखोरी रोककर 58000 करोड़ रुपए का सरकारी धन बचाया गया। **(भाषा)**